

निजी मिलों को प्रतिपूर्ति

का फैसला मंजूर नहीं

Hindustan 02/Sept/2014

Pg-02

राज्य मुख्यालय | प्रमुख संवाददाता

प्रदेश के निजी चीनी मिलों के संगठन उत्तर प्रदेश सुगर मिल एसोसिएशन (यूपीहस्मा) ने घोषणा की है कि उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बीते पेरार्ड सत्र 2013-14 के बकाया गन्ना मूल्य को अदा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई 6 रुपए प्रति कुन्तल की प्रतिपूर्ति स्वीकार नहीं है। सोमवार को जारी बयान में एसोसिएशन की ओर कहा गया है कि राज्य सरकार ने 6 रुपए प्रति कुन्तल की इस प्रतिपूर्ति का निर्धारण किस आधार पर किया है। यह स्पष्ट नहीं है और इस

प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए जो शर्तें लगाई गई हैं वह व्यावहारिक नहीं हैं।

बयान के अनुसार अगले पेरार्ड सत्र के लिए जब तक प्रदेश सरकार डा. रंगराजन समिति के सिफारिशों के अनुसार बाजार में प्रचलित चीनी के मूल्य से गन्ने के भाव को नहीं जोड़ेगी तब तक राज्य की निजी मिलें अगले सत्र के लिए पेरार्ड की तैयारी नहीं करेंगी। बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार ने बगैर निजी मिलों के प्रतिनिधियों से बातचीत किए बिना और उन्हें विश्वास में लिए बगैर 6 प्रति कुन्तल की प्रतिपूर्ति निर्धारित की है।

●●● HINDUSTAN... ●●●

302-09-2014-P-2

✓ R